यू० पी० स्कूटर्स लि० उन्नाव (कानपुर) द्वारा स्कूटरों का निर्माण

621. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स यू० पी० स्कूटर्स उन्नाव (कानपुर) को स्कूटर्स बनाने का लाइसेंस दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्कूटर बिक्री के लिये बाजार में कब तक आ जायेंगे तथा उनका मूल्य कितना होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1974 तक 1 कारखाने से निकलते समय का खुदरा मूल्य जिसमें बिक्री का कमीशन भी सम्मिलित है, प्रति स्कूटर 3720 रुपये होने का अनुमान है ।

Delay in Aluminium Price Revision

622. SHRI S. A. MURUGANANTHAM: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item appearing in the Hindustan Standard dated the 10th October, 1973 captioned "Concern over delay in aluminium price revision"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD): (a) Yes, Sir.

(b) The production of aluminium has been adversely affected in the current year on account of heavy power cuts imposed on the aluminium industry by the different State Electricity Boards. As against the initial estimate of 200,000 tonnes during 1973-74, it is now estimated that production during 1973-74 would be about 140/150,000 tonnes. The fall in production of the metal has affected the availability of the metal to the consuming industry. Steps that are possible to alleviate the scarcity conditions in critical sectors of industry are being taken by Government from time to time.

The cost of production of aluminium and its products (excepting extrusions and foils) is presently being reviewed by the Bureau of Industrial Costs and Prices and decisions on their recommendations regarding selling prices are expected to be taken by Government soon.

Creation of New Posts in Office of Director General of Supplies and Disposals

623. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Miniter of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the DGS&D, Department of Supply continue to waste public money by creating new fangled posts;

(b) whether a new post of Officer-On-Special-Duty for streamlining the DGS&D was sought to be created;

(c) whether a post of Director General is also sought to be created abroad in the Supply Mission in U.K.;

(d) whether any steps have been taken to prevent the creation of these two posts; and

(e) if not, the reasons for not doing this?

THE MINISTER OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): (a) No, Sir. There is no basis for such an allegation.

(b) One temporary post of Officer-On-Special-Duty in the scale of

Rs. 1100—1800 has been created in the Department of Supply from the 18th August, 1973 for a period of six months to assist in streamlining and simplifying the rules, regulations and procedures in the DGS&D.

(c) There is already a post of Director General of the India Supply Mission, London and so the question of creating this post does not arise.

(d) and (e). The implication of this part of the question is not clear. Posts are created according to requirements of work of the Department. Information regarding the two posts is given in reply to parts (b) and (c) above.

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी के लिए स्थान

624. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिये अब तक कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में किसी भी नई भाषा को शामिल करवाना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सरकारी एवं कामकाजी भाषाओं की सूची में किसी भाषा को जोड़ने के लिए, प्रक्रिया के नियमों का संशोधन और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से समर्थन अपेक्षित है। इस बात की सम्भावना नहीं है कि वर्तमान स्थिति में बहुमत इस विषय में किसी भी फेरबदल का समर्थन करेगा।

स्कूटरों का उत्पादन

625. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने स्कूटर कारखाने हैं ;

(ख) विभिन्न कारखानों में स्कूटरों के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत में निर्मित स्कूटरों का विदेशों को निर्यात किया जाता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह): (क) और (ख). इस समय देश में स्कूटरों के चार निर्माता हैं। उनके नाम और 1972 तथा 1973 (सितम्बर तक) स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन निम्नलिखित है:—

नाम	उत्पादन (संख्या)	
	1972	1973 (सितम्बर तक)
मैसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया लि०, बाम्बई	20,851	18,614
मैसर्स बजाज आटो लि०, पूना	40,332	38,755
मैसर्स एस्कार्टस लि०, फरीदाबाद	3,468	2,531
मैसर्स इन्फील्ड इण्डिया लि०, मद्रास	80	कुछ नहीं
योग	64,731	59,000

(ग) स्कूटरों के निर्यात की संख्या बिलकुल ही नगण्य है ।